विनिर्दिष्टियों में ढील देने की अनुमति दी जाए क्योंकि सितम्बर और अक्तूबर 1998 के दोरान बेमौसम वर्षा हुई थी। सरकार इस पर विचार कर रही हैं।

Review of Working of Food Processing Units

1502. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the food processing industry which were sanctioned and set up in the country during Eighth Plan;

(b) the State-wise details of those Food Processing Units;

(c) whether Government have reviewed the working of those units;

(d) if not, whether any study is proposed to be conducted and any action plan proposed to be implemented to strengthen those units; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) and (b) While the Ministry of Food Processing Industries do not set up food processing units directly in any State, under its Plan Schemes it provides financial assistance in the form of loan and grant to private industry, non- overnmental Organisations, Cooperatives and Public Sector Undertakings etc. for the growth, promotion and development of food processing industries. The schemes are project oriented and not State specific. During the 8th Plan period, Plan funds of Rs. 177.11 crore were utilised.

(c) to (e) The work relating to luation of projects funded by the Ministry during 8th Five Year Plan and first year of the Ninth Plan has been entrusted to the National Council of Applied Economic Research in February, 1999 and the work is scheduled to be completed within 6 months. The scope of the study is to find the present status, to review the past performance, to identify the managerial/financial problems; and to suggest corrective action.

Priority Sector benefits to Food Processing Industries

1503. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made the food processing industry a priority sector for bank lending; and

(b) if so, what benefits will accrue to the industry as a result of this decision?

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) As 40% of the net Bank credit of all the Banks is targetted towards the priority sector, easy availability of finance to the food processing sector is ensured.

भारतीय प्रसारण सेवा को हुआ घाटा

1504. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)सरकार द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान भारतीय प्रसारण सेवा क्षेत्रों के प्रति वर्ष कुल कितना राजस्व अर्जन में लगातार गिरावट आयी हैं;

(ख)क्या विदेशी और निजी प्रसारण माध्यमों की तुलना में मंत्रालय के अधीन प्रसारण सेवा के राजस्व अर्जन में लगातार गिरावट आयी हैं;

(ग)यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके द्वारा अर्जित किए गए लाभांश का कुल प्रतिशत कितना रहा; और

(घ)क्या उस स्थिति के बारे में कोई आकलन किया गया है जिसके अन्तर्गत भारतीय प्रसारण सेवा को भारी घाटा हो रहा हैं?

सूचना और प्रससरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) आठवीं योजना के दौरान प्रसार भारती (आकाशवाणी तथा दूरदर्शन) द्वारा अर्जित कुल राजस्व निम्न अनुसार हैं:-

वर्ष	रूपये करोड़ में
1992-93	419.14
1993-94	441.33
1994-95	462.41
1995-96	511.10
1996-97	667.93
	2501.91

(ख)विदेशी तथा निजी प्रसारण माध्यमों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सं संबंधित आंकड़ें चूंकि सरकार के पास उपलब्ध नहीं हें इसलिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की आय सन्दर्भ में कोई तुलना नही की जा सकती है।

(ग)प्रश्न नहीं उठता।

(घ)चूंकि आठवीं योजना में प्रसार भारती की आय में वर्ष-दर-वर्ष लगातार वृद्धि हुई हैं इसलिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

विज्ञापन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

1505.**श्री कपिल सिब्बल** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह :

क्या सूचना और प्रसार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसासर विज्ञापन के क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों को अक्तूबर, 1998 में शत् प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई थी:

(ख)यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में इस नीति मे परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा हैं; और

(ग)यदि हां, तो विचाराधीन संभावित परिवर्तनो का ब्यौरा क्या हैं और पूव नीति में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देश में प्रसारण क्षमता का सृजन और उपयोग

1506. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ययह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या देश मे विभिन्न राज्यों में प्रसारण क्षमता के सृजन और उपयोग मे अत्याधिक अन्तर हैं;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग)क्या सरकार ने इस अन्तर को समाप्त करने हेतु कोई वृहद योजना तैयार की है और इसके लिए कोई मूल्यांकन भी किया है;

(घ)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.)यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में रेडियो कवरेज की उपलब्धता के संबंध में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है तथापि, स्थलीय टेलीविजन कवरेज के मामले में यह अन्तर विद्यमान हैं। राज्य-वार, रेडियो तथा टेलीविजन कवरेज (क्षेत्र एवं जनसंख्यावार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। (**नीचे देखिए**)

(ग)से (ड.) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा यथासंभव अधिकतम दर्शकों को रेडियो/टेलीविजन कवरेज प्रदान करने का सत्त रूप से प्रयास किया जाता हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाओं का समस्त देश में चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जा रहा हैं। रेडियो/टेलीविजन परियोजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय करते समय सम्बन्धित क्षेत्र में विद्यमान रेडिये/टेलीविजन कवरेज एवं लोगों की मांग, आधारभूत सुविधाओं कर उपलब्धता, सीमावर्त्ती, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। देश में रेडियो/टेलीविजिन कवरेज के और विस्तार के लिए वर्तमान में भिन्न-भिन्न क्षमता के 98 रेडियो ट्रांसमीटर तथा 278 टेलीविजिन ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के दौरान कुछ और स्कीमों कोद शुरू करने का विचार हैं।